RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 15 MAY TO 21 MAY 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 34 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

चीन को किनारे करने की तैयारी में...म्यांमार रूस बनाएगा बंदरगाह और तेल रिफाइनरी, Page 2

अमेरिका को टक्कर देने वाला जापान अब भारत से पिछड़ने के करीब Page 3

आप घर पर कितनी शराब रख सकते हैं? हरेक राज्य की अलग लिमिट Page 4

editorial!

दूरगामी समझौता

भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह की देखभाल, विकास और संचालन को लेकर सोमवार को हुआ समझौता न सिर्फ दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से अहम है बल्कि आने वाले वर्षों में इस पूरे क्षेत्र की भू-राजनीति को भी निर्णायक ढंग से प्रभावित कर सकता है। इस समझौते के प्रयास काफी पहले से चल रहे थे। चाबहार को लेकर दोनों देशों में पहला समझौता 2016 में हुआ। 2018 में तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी की भारत यात्रा के दौरान इस पोर्ट पर भारत की भूमिका बढ़ाने का मसला प्रमुखता से उठा। बाद में कोविड-19 महामारी और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते यह प्रक्रिया कुछ धीमी पड़ी, लेकिन आखिरकार समझौता हो गया। समझौते का एक अहम पहलू यह है कि इससे पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह ही नहीं, चीन के बेल्ट एंड रोड इनीशटिव को भी बैलेंस करने में मदद मिल सकती है। भारत चाबहार पोर्ट की बदौलत पाकिस्तान को बाइपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बना सकता है। पाकिस्तान मध्य एशियाई देशों को इस बात के लिए लुभाने की कोशिश करता रहा है कि वे हिंद महासागर क्षेत्र तक पहुंच बनाने के लिए कराची बंदरगाह का इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ भारत इस तथ्य को समझ रहा था कि चाबहार बंदरगाह उन देशों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। अब इस संभावना को ठोस रूप देना आसान होगा। समझौते की टाइमिंग भी इसे संवेदनशील बना रही थी। पश्चिम एशिया संकट के दौरान ईरान और इस्राइल के बीच बढ़े तनाव के मद्देनजर अमेरिका ने ईरान पर नए सिरे से आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में भारत के लिए सभी संबंधित पक्षों को विश्वास में लेते हुए ईरान के साथ एक दीर्घकालिक समझौते को अंतिम रूप देना चुनौतीपूर्ण था। समझौते की घोषणा के बाद अमेरिका ने हालांकि यह कहते हुए परोक्ष चेतावनी दी कि जो कोई भी ईरान के साथ किसी तरह के समझौते में जाता है, उसे इसमें निहित संभावित प्रतिबंधों के खतरे से वाकिफ होना चाहिए। लेकिन इस बयान का स्वरूप भी बता देता है कि यह औपचारिकता ज्यादा है और चेतावनी कम। इस मामले में विदेश मंत्री जयशंकर का यह कहना ज्यादा अहम है कि अमेरिका को इससे कोई दिक्कत नहीं है। जयशंकर के बयान का अगला हिस्सा विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने कहा कि 'वैसे भी मेरे और ईरान के बीच में अगर कुछ होता है तो वह मेरे और ईरान के बीच की बात है।' जाहिर है, भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित स्वतंत्र नीति की अपनी राह से विचलित नहीं होने वाला।

मध्यप्रदेश सरकार ले सकती है कुछ कठोर फैसले

15 जुलाई को आ सकता है बजट

भोपाल। आईपीटी नेटवर्क

राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान समाप्त होने और आचार संहिता हटने की संभावना के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए फिर से काम पर लग गई है। सरकार ने 2024-25 के लिए काम शुरू कर दिया है। आम चुनावों के कारण, इस साल फरवरी-मार्च में सरकार ने पूर्ण बजट पेश नहीं किया और केंद्र सरकार की तर्ज पर इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही को संभालने के लिए वोट ऑन अकाउंट लाया। राज्य का बजट 31 जुलाई से पहले पेश किया जाना चाहिए।

15 जुलाई के आसपास आ सकता है बजट

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि राज्य का बजट 15 जुलाई के आसपास पेश होने की उम्मीद है। जुलाई में बजट में एक नया कर भी लगाया जा सकता है, हालांकि इसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव और उसके बाद आम चुनाव होने के कारण, सरकार ने नरमी बरती और करदाताओं पर कोई नया कर लगाने से परहेज किया।

पांच साल बाद हैं अब चुनाव

राज्य में अगला विधानसभा और आम चुनाव चार से पांच साल बाद होगा। सरकार इस समय को कुछ कठोर वित्तीय फैसले लेने के लिए आदर्श मान रही है। वित्त विभाग ने गुरुवार को बजट अनुमानों के बारे में सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्ण बजट के बजाए लेखानुदान पेश करने का कारण यह है कि राज्य को केंद्र सरकार की तरफ राज्यांश मिलने में देरी है। केंद्र सरकार ने भी लेखानुदान का विकल्प चुना है और वह जुलाई में अपना पूर्ण बजट पेश कर सकती है।

फरवरी में सरकार ने पेश किया था लेखानुदान

फरवरी में सरकार ने राज्य विधानसभा में 2024-25 के लिए लेखानुदान पेश किया था। लेखानुदान का उद्देश्य मुख्य बजट पारित होने तक सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को जारी रखने के लिए समेकित निधि से धन निकालना था। कराधान और व्यय के नए शीर्षों से संबंधित नए प्रस्तावों को लेखानुदान में शामिल नहीं किया गया।

तीन लाख करोड़ के पार हो सकता है बजट

लेखानुदान के ज़रिए मिलने वाला पैसा मुख्य बजट का हिस्सा होगा। लेखानुदान 1,45,229 करोड़ रुपये का था। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट का अनुमान भी दिया जो 3,48,986.57 करोड़ है। अगले वित्त वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियां 2,52,268.03 करोड़ रुपये आंकी गई हैं, जिसमें से राज्य कराधान से आय 96,553.30 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सूत्रों ने बताया कि गैर-कर राजस्व 18,077 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

देश में बेरोजगारी दर में आई गिरावट, रोजगार में बढ़ोतरी के संकेत

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति बेहतर

एजेंसी

देश में बेरोजगारी दर में कमी का रुझान देखा गया है। भारत के शहरी क्षेत्रों में जनवरी-मार्च 2024 के दौरान 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर पिछले वर्ष की समान अवधि में 6.8 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई, जो निरंतर सुधार को दर्शाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा बीते बुधवार को जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों से यह पता चला। ध्ंए की खबर के मुताबिक, आंकड़े बताते हैं कि शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2023 में 9.2 प्रतिशत से घटकर जनवरी-मार्च 2024 में 8.5 प्रतिशत हो गई।

शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात बढ़ा

खबर के मुताबिक, 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में भी जनवरी-मार्च 2023 में 45.2 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी-मार्च 2024 में 46.9 प्रतिशत होने का ट्रेंड देखा गया है। यह आंकड़े रोजगार में बढ़ोतरी को भी दर्शाता है, क्योंकि डब?ल?यूपीआर को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात जनवरी-मार्च 2023 से जनवरी-मार्च 2024 तक 20.6 प्रतिशत से बढ़कर 23.4 प्रतिशत हो गया, जो डब्ल्यूपीआर में कुल मिलाकर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

जॉब मार्केट में सुधार

शहरी क्षेत्रों में श्रमबल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए जनवरी-मार्च 2023 के दौरान 48.5 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी-मार्च 2024 में 50.2 प्रतिशत हो गई है। यह जॉब मार्केट में सुधार को भी दर्शाता है। इसी साल जनवरी में बेरोजगारी दर पिछले 16 महीनों में सबसे कम दर्ज की गई। हालांकि, 20 से 30 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर में 2023 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

फोर्ब्स के मुताबिक 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर बढ़कर 44.49 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई-सितंबर तिमाही में 43.65 प्रतिशत थी। इसी तरह, 25 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 2023 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़कर 14.33 प्रतिशत हो गई, जो पिछली तिमाही में 13.35 प्रतिशत थी।

चीन को किनारे करने की तैयारी में म्यांमार

रूस बनाएगा बंदरगाह और तेल रिफाइनरी, भारत को मिली बड़ी राहत

नेपीडा। एजेंसी

म्यांमार के जुंटा शासन ने रूस की मदद से देश के पूर्वी तट पर दावेई बंदरगाह बनाने के लिए रूस की मदद लेने का फैसला लिया है। जुंटा के इस फैसले ने चीन को नाराज कर दिया है, जो थाईलैंड सीमा के करीब स्थित बंदरगाह का निर्माण करने पर नजर गड़ाए हुए था। म्यांमार जुंटा रूसियों को तेल रिफाइनरी सहित एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ बंदरगाह परियोजना में निवेश कराने के लिए उत्सुक है। ईटी के मुताबिक, चीन काफी समय से दावेई बंदरगाह पर प्लान कर रहा था लेकिन उसने इस पर ठंडे कदम उठाए। इसकी वजह चीन का ध्यान भारत निर्मित सितवे बंदरगाह के नजदीक क्याकफ्यू गहरे बंदरगाह के निर्माण पर केंद्रित था। म्यांमार के विशेषज्ञों के अनुसार, रूस के प्रति झुकाव के लिए जुंटा को चीनियों के क्रोध का सामना करना पड़ा है।

म्यांमार (अंडमान सागर) के पूर्वी तट पर तनिनथारी क्षेत्र में प्रस्तावित दावाई बंदरगाह कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और चीन सहित ग्रेटर मेकांग (जीएमएस) देशों का गेट है। यह पोर्ट थाईलैंड कंटेनरीकृत व्यापार के लिए प्रवेश द्वार भी बन सकता है। बैंकॉक दावेई से 300 किलोमीटर दूर है और दोतरफा कंक्रीट सड़क से जुड़ा हुआ है। संसाधन संपन्न म्यांमार में चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिए म्यांमार और रूस प्रस्तावित बंदरगाह पर चर्चा कर रहे हैं। म्यांमार और रूस की बातचीत में दावेई बंदरगाह (10 मिलियन टन क्षमता) और एक तेल रिफाइनरी (100,000 बैरल/दिन) बनाने के प्रस्ताव हैं। बीजिंग इस बात से नाराज़ है कि म्यांमार में बंदरगाह क्षेत्र में रूस के प्रवेश से क्षेत्र में वैश्विक व्यापार के दायरे में क्याउकफ्यू में चीनी परियोजनाएं कमजोर हो जाएंगी।

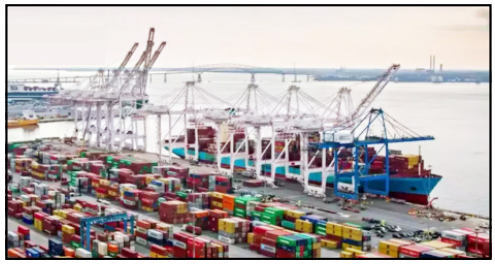

भारत के लिए ये राहत की खबर!

भारत इस बात से सहज हो सकता है कि म्यांमार चीन की तुलना में रूस के करीब जा रहा है। म्यांमार भारत के लिए बेहद अहम रहा है। भारत ने म्यांमार को रूसी मूल की पनडुब्बियां भी दी हैं। इसके अलावा श्रीलंका में भारत और रूसी कंपनियों ने चीनी प्रबंधित हंबनटोटा बंदरगाह के पास एक हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाया है। ईटी ने मार्च में रिपोर्ट दी थी कि म्यांमार जुंटा ने बीजिंग पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करने की मांग की है और सैन्य आपूर्ति हासिल करने और बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के लिए रूस के साथ संबंधों का विस्तार कर रहा है।

पिछले साल म्यांमार ने विद्रोही समूहों के खिलाफ अपनी वायु सेना को शक्ति देने के लिए रूस से तेल आयात बढ़ा दिया था। साझेदारी के बढ़ते प्रक्षेप पथ से परिचित लोगों के अनुसार, जुंटा के नेतृत्व वाली सरकार ने 2023 में मार्च और जून के बीच 8 मिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल का आयात किया। पिछले अक्टूबर से म्यांमार की सेना और जातीय समूहों के बीच लड़ाई तेज होने के बाद से म्यांमार-रूस रक्षा सहयोग में तेजी आई है। सितवे नौसैनिक अड्डे के प्रमुख ने नौसेना के लिए उपकरण खरीदने के लिए पिछले अक्टूबर में रूस का दौरा किया था और पहला समुद्री सुरक्षा अभ्यास पिछले नवंबर में आयोजित किया गया था। सितवे नौसैनिक अड्डे के प्रमुख की रूस यात्रा के दौरान 35 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

रूस से म्यांमार को मिल रहे सैन्य सामान

रूस म्यांमार को सैन्य हार्डवेयर के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है, जिसमें सुखोई लड़ाकू जेट और रॉकेट लॉन्चर सहित 406 मिलियन डॉलर के अन्य उपकरण शामिल हैं। फरवरी 2021 में तख्तापलट के बाद सत्ता संभालने के बाद से म्यांमार जुंटा प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग ने तीन बार रूस का दौरा किया है। 2022 में म्यांमार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का संवाद भागीदार बनाया गया था।

यह भी बताया था कि रूस दो निजी सैन्य कंपनियों - वैगनर और वेगा स्ट्रैटेजिक सर्विसेज के माध्यम से स्नाइपर और ड्रोन प्रशिक्षण में म्यांमार की सहायता कर रहा है और उनके विशेषज्ञ देश के उन हिस्सों सहित म्यांमार में जमीन पर मौजूद हैं जहां जातीय समूहों की सक्रिय उपस्थिति है।

दिलचस्प बात यह है कि रूसी परमाणु प्रमुख रोसाटॉम म्यांमार को छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर प्रदान कर सकता है। फरवरी 2023 में, मास्को की सहायता से यांगून में पहला परमाणु प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र खोला गया।

मेक इन इंडिया का दमदार असर!

64.56 अरब डॉलर का सामान निर्यात कर दुनिया की दुकान बनने की ओर बढ़ रहा भारत

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

'मेक इन इंडिया' अभियान की बदौलत भारत निर्यात के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2024 में भारत ने 64.56 अरब डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया, जो पिछले साल अप्रैल की तुलना में 6.88% की शानदार वृद्धि दर्शाता है। यह आंकड़ा देश की निर्यात क्षमता और 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

निर्यात में बढ़ोतरी के प्रमुख कारणः

विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धिः अप्रैल में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, रत्न और आभूषण, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों से निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सेवा क्षेत्र का मजबूत प्रदर्शनः सेवा क्षेत्र ने भी निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका मूल्य अप्रैल 2024 में 341.1 अरब डॉलर रहा।

वैश्विक बाजारों में भारत की मजबूत स्थितिः भारत ने कई वैश्विक बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत की है, जिससे विदेशी खरीदारों की मांग में वृद्धि हुई है।

हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं:

व्यापार घाटाः अप्रैल में आयात भी बढ़कर 54.09 अरब डॉलर हो गया, जिससे व्यापार घाटा 19.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धाः वैश्विक बाजारों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा भारत के लिए एक चुनौती है। कुल मिलाकर, अप्रैल 2024 के निर्यात आंकड़े भारत के लिए उत्साहजनक हैं। 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत देश निर्यात के मामले में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की राह पर है। हालांकि, व्यापार घाटा कम करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक बने रहने के लिए अभी भी कुछ काम करने की आवश्यकता है।

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने भारत में कराया रजिस्ट्रेशन

फिर से ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी

एजेंसी

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनान्स ने भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्ट्रेशन कराया है। एक्सचेंज का इरादा इस देश में फिर से अपना ऑपरेशन शुरू करने का है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (इफ्ळ) के एक सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक्सचेंज को दिसंबर में भारत में कारोबार करने से रोक दिया गया था। स्थानीय कानून का पालन नहीं करने के मामले में यह कार्रवाई की गई थी। फाइनेंशियल रेगुलेटर ने उन ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कार्रवाई की थी, जो बिना रजिस्ट्रेशन के भारत में काम कर रहे थे।

भारत में ऑपरेशन शुरू करने के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स मसलन क्रिप्टो एक्सचेंजों को इफ्ळ के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। साथ ही, देश के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के प्रावधानों का भी पालन सुनिश्चित करने की जरूरत होती है। इफ्ळ के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल ने बताया कि बिनान्स ने भले ही इफ्ळ के साथ रजिस्ट्रेशन कराया हो, लेकिन यह ऑपरेशन तभी शुरू कर करेगा, जब नियमों का पालन नहीं करने के मामले में पेनाल्टी का भुगतान करेगा।

इफ्ळ ने दिसंबर 2023 में 9 ऑफशोर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यह नोटिस स्थानीय कानून के उल्लंघन के मामले में जारी किया गया था। फाइनेंशियल रेगुलेटर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और घ्ळ मिनिस्ट्री से एक्सचेंजों का ऑनलाइन एक्सेस ब्लॉक करने को भी कहा था।

अग्रवाल ने बताया कि ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंज ख्ल्ण्दग ने भी इफ्ळ के साथ रजिस्ट्रेशन कराया था और 34.5 लाख रुपया जुर्माना भरने के बाद ऑपरेशन फिर से शुरू किया था। ख्ल्ण्दग ने मार्च में रजिस्ट्रेशन का ऐलान किया था, लेकिन पेनाल्टी के बारे में जानकारी साझा नहीं की थी।

तीन हफ्ते गिरने के बाद देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.66 अरब डॉलर बढ़ा

नई दिल्ली। एजेंसी

पिछले तीन सप्ताह की गिरावट के बाद देश का विदेशी मुद्रा भंडार तीन मई को समाप्त सप्ताह में 3.67 अरब डॉलर बढ़ा। यह बढ़कर 641.59 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पहले 26 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.41 अरब डॉलर घटकर 637.92 अरब डॉलर रहा था। यह कई सप्ताह की तेजी के बाद पांच अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 648.56 अरब डॉलर के नए सर्वकालिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। उधर, 3 मई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा हुआ है। यह 1.1 अरब डॉलर बढ़कर 9.1 अरब डॉलर हो गया।

FCA में 4.46 अरब की बढ़ोतरी

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, तीन मई को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां (FCA) 4.46 अरब डॉलर बढ़कर 564.16 अरब डॉलर रहीं। इन्हीं का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कर्ज चुकाने और देश की मुद्रा को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। यह जितना अधिक होता है, देश के लिए उतना ही अच्छा होता है। इसका मतलब है कि देश के पास अंतरराष्ट्रीय भुगतान करने और आर्थिक झटकों का सामना करने की अधिक क्षमता है।

गोल्ड रिजर्व का मूल्य घटा

डॉलर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है।

हम समझते हैं कंप्यूटर बाहर से लाते हैं, देखिए हमारा कितना बढ़ गया निर्यात

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत में कई चीजों के निर्यात में काफी उछाल देखने को मिला है। भारत सरकार कई दूसरी कंपनियों को लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो देश में ही चीजें बनाए और चीन पर निर्भरता कम हो सके। भारत ने एप्पल और सैमसंग जैसी कई कंपनियों को आकर्षित किया है। वहीं स्मार्टफोन और दूसरे महंगे सामानों के एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन, कुछ ऐसे सामान भी हैं जिनका एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा है, भले ही वो हाई-टेक न हों। इसके सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बालों का बढ़ा है। बालों का निर्यात कोरोना काल से पहले साल 2018-19 में करीब 34.5 मिलियन डॉलर था। यह पिछले साल बढ़कर करीब 180 मिलियन डॉलर हो गया है। इसमें 5 गुना से ज्यादा उछाल

आई है। टेलीकॉम, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में 170.9 फीसदी का उछाल आ चुका है।

खूब बढ़ा निर्यात

इसी तरह, एक खास तरह के तांबे के तारों का एक्सपोर्ट $76 मिलियन से बढ़कर $867 मिलियन हो गया है। ये 11 गुना का इजाफा है। वहीं मूंगफली के तेल का एक्सपोर्ट तो 2018-19 में लगभग ना के बराबर था, जो पिछले साल $217 मिलियन हो गया है। स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट भी दस गुना बढ़ा है। साल 2019 वित्तीय वर्ष में यह $1.6 बिलियन था जो 2024 में $15.5 बिलियन हो गया है। सरकारी नीतियों की वजह से यह मुमकिन हुआ है।

इन देशों में बढ़ा है एक्सपोर्ट

तुर्की, अमेरिका और ब्रिटेन में पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा बढ़ा है। कुल मिलाकर पिछले वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सपोर्ट 23.6% बढ़कर $29 बिलियन से ज्यादा हो गया है। लोहे की धात का एक्सपोर्ट भी दोगुना से ज्यादा बढ़कर $3.9 बिलियन हो गया है। पिछले पांच सालों में उबले हुए चावल का एक्सपोर्ट भी दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। साल 2019 में यह $1.5 बिलियन था जो पिछले साल $3.3 बिलियन हो गया। वहीं कैंसर की दवाइयों का एक्सपोर्ट भी तीन गुना बढ़कर $1.5 बिलियन से ज्यादा हो गया है। गाड़ियों का एक्सपोर्ट भी 43% बढ़कर $4.3 बिलियन हो गया है। लेकिन, हीरे और कपड़े जैसे कुछ पारंपरिक चीजों का एक्सपोर्ट कम हुआ है। हीरों का एक्सपोर्ट पांच सालों में एक तिहाई घटकर $23.7 बिलियन हो गया है। कॉटन की टी-शर्ट का एक्सपोर्ट 15% घटकर $1.6 बिलियन रह गया है। चमड़े का एक्सपोर्ट भी 11% घटकर $2.5 बिलियन रह गया है।

आरबीआई का नया अपडेट आया सामने!

लागू कर दिया अब यह नया नियम

नई दिल्ली। एजेंसी

नकद ऋण के संबंध में, आरबीआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सोने के बदले ऋण देते समय 20,000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान नहीं करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश आयकर अधिनियम की धारा 269 एस टी के अनुसार दिया गया है।

आयकर अधिनियम की यह धारा यह प्रावधान करती है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से 20,000 रुपये से अधिक नकद जमा या ऋण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस के निरीक्षण में कुछ चिंताएं पाए जाने के बाद इसे स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने और वितरित करने से रोक दिया।

मणप्पुरम फाइनेंस के सीईओ वी.पी. नंदकुमार ने कहा है कि इस निर्देश में नकद ऋण देने की 20,000 रुपये की सीमा को दोहराया गया है। उन्होंने कहा कि मणप्पुरम फाइनेंस के अधिकांश ऋण ऑनलाइन वितरित किए जाते हैं और शेष वितरण भी शाखाओं से किए जाते हैं।

अमेरिका को टक्कर देने वाला जापान अब भारत से पिछड़ने के करीब

नई दिल्ली। एजेंसी

एक जमाना था कि जब यह माना जा रहा था कि जापान की इकॉनमी अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। लेकिन आज जापान दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में चौथे नंबर पर खिसक चुका है। पहले चीन ने और फिर जर्मनी उससे आगे निकल गए। अब भारत के भी जल्दी ही जापान को पछाड़ने का अनुमान है। आईएमएफ का कहना है कि 2025 में डॉलर टर्म में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। भारत की इकॉनमी का साइज 4.34 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगा जबकि जापान की इकॉनमी 4.31 ट्रिलियन डॉलर रह जाएगी। साल 2010 तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी था। केवल अमेरिका ही उससे आगे था। लेकिन अब जापान पर पांचवें नंबर पर खिसकने का खतरा मंडरा रहा है। आखिर क्यों आई ऐसी नौबत?जापान की इकॉनमी किसी जमाने में रॉकेट की स्पीड से भाग रही थी और माना जा रहा था कि वह अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। आज से 30 साल पहले जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी था। तब भारत उसके सामने कहीं नहीं टिकता था। 1993 में जापान की इकॉनमी का साइज 4.54 ट्रिलियन डॉलर था जबकि भारत की इकॉनमी 280 अरब डॉलर की थी। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में जापान की इकॉनमी में सुस्ती का ऐसा दौर आया कि वह आज तक इससे उभर नहीं पाया है। साल 2010 में जापान को पछाड़कर चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया। पिछले साल जर्मनी ने जापान को चौथे नंबर पर धकेल दिया। बैंक ऑफ जापान ने स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए साल 2016 में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट शुरू किया था। इससे दुनियाभर के निवेशकों के लिए येन आकर्षित नहीं रह गया। इससे येन की वैल्यू में और कमी आई।

ऑस्ट्रेलिया भेड़ों के निर्यात पर लगाने जा रहा रोक

नई दिल्ली। एजेंसी

अब आस्ट्रेलिया समुद्र के रास्ते होने वाले जीवित भेड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने समुद्री रास्ते भेड़ों के निर्यात पर 2028 से पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला जानवरों के हितों की रक्षा करने वाले समूहों की मांग पर लिया गया है। सरकार का कहना है कि निर्यात बंद करने से पहले पांच सालों में 10.7 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की राशि से सहायता दी जाएगी ताकि इससे प्रभावित होने वाले लोग समायोजन कर सकें। हालांकि पशु किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन इस फैसले से खुश नहीं है। उनका कहना है कि इससे कई लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और किसान समुदाय प्रभावित होंगे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार के मुताबिक, वह मई 2028 से समुद्र के रास्ते देश से जीवित भेड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगी। प्रतिबंध लागू करने के लिए कानून संघीय संसद के वर्तमान कार्यकाल में पेश किया जाएगा। यह चरणबद्ध प्रतिबंध पशुधन निर्यात उद्योगों, जैसे जीवित मवेशियों के निर्यात पर लागू नहीं होती है और न ही यह हवाई मार्ग से जीवित भेड़ों के निर्यात पर लागू होती है।

कितना बड़ा है कारोबार

गौरतलब है कि 1990 और 2000 के दशक में ऑस्ट्रेलिया हर साल लगभग 50 लाख भेड़ों का निर्यात करता था, लेकिन धीरे-धीरे यह संख्या कम होती चली गई। अब यह संख्या कम होकर 6 लाख 84 हजार हो गई है। इनकी कीमत लगभग 50 मिलियन डॉलर थी। इन भेड़ों को जहाजों से मुख्यतः मध्य-पूर्व के देशों में भेजा जाता है। जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले समूहों का कहना है कि भेड़ों को इतनी लंबी यात्रा कराना उनके साथ क्रूरता है। 2018 में गर्मी से 2400 भेड़ों की मौत के बाद से इस मामले को लेकर काफी बहस छिड़ी थी।

आप घर पर कितनी शराब रख सकते हैं?

हरेक राज्य की अलग लिमिट

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में घर पर रखने वाली शराब की मात्रा हर राज्य में अलग-अलग है। कुछ राज्यों में इसकी मात्रा तय की गई है, जबकि कई राज्यों में लाइसेंस लेकर ज?यादा शराब रखने की छूट है। यह मात्रा सिर्फ व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है। अगर आप पार्टी के लिए ज?यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा। शराब की खरीद, परिवहन और कब्जे के लिए भी नियम हैं। इस तरह का सवाल खासतौर से तब खड़ा होता है जब दोस्त घर आ रहे हों या घर पर आप कोई पार्टी दे रहे हों। तब हर कोई यही सोचता है कि कितनी शराब काफी होगी। लेकिन, लिमिट से ज?यादा शराब घर पर रखना महंगा पड़ सकता है। आइए, यहां जानते हैं कि बिना किसी कानूनी पचड़े के आप घर पर कितनी शराब रख सकते हैं।

दिल्ली: दिल्लीवासी घर पर 18 लीटर तक शराब (बीयर और वाइन सहित) रख सकते हैं। वे 9 लीटर से अधिक रम, व्हिस्की, वोदका या जिन नहीं रख सकते हैं। सिर्फ एक लीटर शराब ही दिल्ली से बाहर ले जाई जा सकती है।

हरियाणा: स्टॉक सीमा में स्थानीय शराब की 6 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली), आईएमएफएल की 18 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली, 6 से अधिक आयातित विदेशी शराब नहीं), 12 बीयर की बोतलें (650 मिली), 6 रम की बोतलें (750 मिली), 6 वोदका/साइडर/जिन बोतलें (750 मिली) और 12 वाइन बोतलें शामिल हैं।

पंजाब: निवासियों को भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की दो बोतलें, बीयर का एक केस (प्रति बोतल 650 मिलीलीटर), किसी भी विदेशी शराब की दो बोतलें (1 या 5 लीटर), घरेलू शराब की दो बोतलें और ब्रांडी की एक बोतल रखने की अनुमति है।

उत्तर प्रदेश: विदेशी मादक पेय पदार्थों (भारत में निर्मित और आयातित दोनों) की कानूनी सीमा 1.5 लीटर है। वाइन के लिए सीमा 2 लीटर है और बीयर के लिए यह 6 लीटर है।

आंध्र प्रदेश: निवासियों को बिना किसी परमिट के भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) या विदेशी शराब की अधिकतम तीन बोतलें और बीयर की अधिकतम छह बोतलें रखने की अनुमति है।

अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत वैध शराब लाइसेंस के बिना 18 लीटर से अधिक आईएमएफएल या देशी शराब रखना अवैध है।

पश्चिम बंगाल: 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को भारत में निर्मित विदेशी शराब की अधिकतम छह बोतल खरीदने और रखने की अनुमति है, जिनमें से प्रत्येक में 750 मिली लीटर शराब होती है। इसके अलावा उन्हें बिना लाइसेंस के 18 बीयर की बोतल रखने की इजाजत है।

असम: खुदरा बिक्री प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आईएमएफएल की 12 बोतलों, संशोधित या विकृत स्पिरिट की 4.5 लीटर तथा 'प्रतिष्ठित' देशी स्पिरिट की 3 बोतलों (750 मिली प्रत्येक) तक सीमित है।

गोवा: निवासियों को अधिकतम 12 बोतल भारतीय विदेशी शराब, 24 बोतल बीयर, 18 बोतल देशी शराब तथा रेक्टीफाइड व डिनेचर्ड स्पिरिट की 6-6 बोतल रखने की अनुमति है।

हिमाचल प्रदेश: लोगों को अधिकतम 48 बीयर की बोतलें और 36 व्हिस्की की बोतल रखने की इजाजत है।

केरल: शराब की अधिकतम अनुमत खपत 3 लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और 6 लीटर बीयर है।

मध्य प्रदेश: उच्च आय वाले व्यक्ति एक वार्षिक शुल्क देकर अपने घर में 100 'महंगी' शराब की बोतलें रख सकते हैं।

महाराष्ट्र: शराब पीने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। आपके पास स्थानीय और आयातित दोनों तरह की शराब खरीदने, परिवहन करने और पीने के लिए परमिट होना चाहिए।

राजस्थान: नागरिकों को 12 बोतल या नौ लीटर आईएमएफएल रखने की अनुमति है।

जम्मू और कश्मीर: अनुमत भंडारण में भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की 12 बोतलें शामिल हैं, जिनमें 750 मिलीलीटर जेके देसी व्हिस्की और 12 बीयर की बोतल शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 650 मिलीलीटर है।

ड्राय स्टेट्स: मिजोरम, गुजरात, बिहार, नागालैंड और लक्षद्वीप जैसे शराबबंदी वाले राज्यों में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कानून को तोड़ने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

सोलापुर के बाद अब राहुरी में 100 रुपये क्विंटल हुआ प्याज का दाम, चिंता में डूबे किसान

नाशिक। एजेंसी

निर्यातबंदी खत्म होने के 12 दिन बाद भी महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज के दाम में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। सोलापुर के बाद अब राहुरी मंडी में भी किसानों को मिलने वाले प्याज का न्यूनतम दाम सिर्फ 100 रुपये क्विंटल रह गया है। सोलापुर में तो लगातार किसानों को न्यूनतम दाम सिर्फ 100 रुपये क्विंटल ही मिल रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 550 डॉलर प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य और उस पर लगे 40 प्रतिशत शुल्क को खत्म नहीं करेगी तब तक किसानों को निर्यात खोलने का कोई लाभ नहीं मिलेगा।क्योंकि महंगा होने के कारण निर्यात खुलने के बावजूद प्याज निर्यात नहीं हो पा रहा है। इसलिए राज्य की मंडियों में प्याज की आवक बढ़ गई है, जिससे दाम गिर गए हैं। किसान इस चिंता में डूबे हुए हैं कि खरीफ के बाद रबी सीजन में भी दाम सही नहीं मिल रहा है ऐसे में आगे वो खेती कैसे करेंगे।

किसानों को उम्मीद थी कि जब निर्यातबंदी खत्म होगी तब राज्य की किसी भी मंडी में किसी किसान को 1 और 2 रुपये किलो के दाम पर प्याज नहीं बेचना पड़ेगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी। सरकार ने 4 मई को निर्यातबंदी खत्म की. तब 5 और 6 मई को दाम बढ़े थे लेकिन उसके बाद फिर पहले की तरह गिरावट आ गई। केंद्र सरकार ने प्याज की महंगाई को कम करने के लिए 7 दिसंबर 2023 को प्याज की निर्यातबंदी कर दी थी। उससे पहले दाम कंट्रोल में करने के लिए 800 डॉलर प्रति टन की एमईपी लगाई थी. उससे भी पहले अगस्त 2023 में 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया था।

कितनी आती है लागत, कितना है दाम

महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अनुसार 2014 में ही प्याज की उत्पादन लागत लगभग साढ़े सात रुपये किलो आती थी। उसके बाद एग्रीकल्चर इनपुट की लागत बहुत तेजी से बढ़ी है। इसलिए अब प्रति किलो लागत 16 से 20 रुपये किलो तक हो गई है। जबकि महाराष्ट्र की अधिकांश मंडियों में इस समय प्याज का दाम 1, 2 रुपये किलो से लेकर 15-16 रुपये किलो तक ही मिल रहा है। जिसकी वजह से किसानों को प्याज की खेती में घाटा हो रहा है। घाटे के कारण ही महाराष्ट्र के किसान प्याज की खेती को अब कम कर रहे हैं।

किस मंडी में कितना है दाम

धुले मंडी में 15 मई को 2113 क्विंटल प्याज की आवक हुई थी। इसके बाद भी यहां प्याज का न्यूनतम दाम 200, अधिकतम दाम 1430 और औसत दाम 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया।

पथरडी में क्विंटल 341 प्याज की आवक दर्ज की गई। इस मंडी में न्यूनतम दाम 200, अधिकतम 1500 और औसत दाम 1000 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

येओला के कोपरगांव में 500 क्विंटल प्याज की आवक हुई। यहां पर न्यूनतम दाम 300, अधिकतम 1531 और औसत 1300 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

धुले ज़िले मंडी में 248 क्विंटल प्याज की आवक हुई। यहां पर न्यूनतम दाम 200, अधिकतम 1430 और औसत दाम 1200 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

देश गर्मी से बेहाल, राहत लेकर केरल तट पर 31 मई को पहुंचेगा मानसून, IMD ने बताई तारीख

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को घोषणा की है कि मौजूदा जलवायु पूर्वानुमानों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून 31 मई के आसपास केरल तट पर पहुंचने की उम्मीद है। यह बारिश के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून की वास्तविक शुरुआत 27 मई से 4 जून के बीच हो सकती है। आमतौर पर, दक्षिण-पश्चिम मानसून 1 जून को केरल में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार यह एक हफ्ते पहले या बाद में आ सकता है।

मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी IMD ने अपने ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के +/- 4 दिनों की मॉडल त्रुटि के साथ 31 मई को केरल में पहुंचने की संभावना है। ध्श्ः के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि यह देरी नहीं है, यह सामान्य तारीख के करीब है क्योंकि केरल में मानसून की शुरुआत की सामान्य तारीख 1 जून है। दक्षिण-पश्चिम मानसून एक मौसमी हवाओं का पैटर्न है जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण बारिश लाता है। यह भारत की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की अधिकांश सालाना बारिश इसी से होती है। जून और जुलाई को कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानसून महीने माना जाता है क्योंकि इस अवधि में खरीफ फसल की अधिकांश बुआई होती है। मानसून दक्षिण-पश्चिम से चलता है, आमतौर पर जून की शुरुआत में केरल पहुंचता है और सितंबर के अंत तक वापस चला जाता है। ध्श्ः के अनुसार, इस साल मानसून सीजन के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। पिछले साल, मानसून की शुरुआत अनुमानित तारीख से चार दिन की देरी से 8 जून को हुई थी।

चुनावों के बाद 25 प्रतिशत बढ़ सकता है आपके मोबाइल का बिल, जान लीजिए क्या है इसकी वजह

नई दिल्ली। एजेंसी

मोबाइल फोन यूजर्स को आम चुनावों के बाद जोर का झटका लग सकता है। उनके बिल में करीब 25ः की बढ़ोतरी हो सकती है। टेलिकॉम कंपनियां हाल के वर्षों में चौथी बार टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में हैं। 2019 से 2023 के बीच इन कंपनियों ने तीन बार टैरिफ में बढ़ोतरी की थी। इससे उनके प्रति यूजर एवरेज रेवेन्यू (ARPU) में तेजी आएगी। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस कैपिटल की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेलिकॉम कंपनियां जल्दी ही टैरिफ में उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर सकती हैं। इन कंपनियों ने 5जी पर भारी निवेश किया है और अब उन्हें अपना मुनाफा बढ़ाने की जरूरत है। इससे शहरी परिवारों के लिए टेलीकॉम पर पर ग्राहकों का खर्च कुल व्यय के 3.2% से बढ़कर 3.6% हो जाएगा, जबकि ग्रामीण ग्राहकों के लिए यह 5.2% से बढ़कर 5.9% हो जाएगा।एक्सिस कैपिटल ने अनुमान लगाया है कि टैरिफ में लगभग 25% की बढ़ोतरी से टेलिकॉम कंपनियों के लिए ARPU में 16% की बढ़ोतरी होगी। भारती एयरटेल के लिए यह 29 रुपये और जियो के लिए 26 रुपये होगी। देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी जियो ने मार्च तिमाही के लिए 181.7 रुपये का ARPU दर्ज किया। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) के लिए अक्टूबर-दिसंबर 2023 की अवधि के लिए यह क्रमशः 208 रुपये और 145 रुपये रहा था। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अब तक मार्च तिमाही के आंकड़े जारी नहीं किए हैं।

नौ साल में एग्री स्टार्टअप कई गुना बढ़कर 7,000 के पार, क्या हैं संकेत?

नई दिल्ली। एजेंसी

कारोबार के अनुकूल माहौल और सरकार के समर्थन के कारण पिछले नौ साल में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्टअप की संख्या 7,000 से अधिक हो गई है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशंस (ईईई) की ओर से बुधवार को जारी 'भारत के कृषि परिवर्तन' शीर्षक वाली रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2014-15 से पहले कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 50 से भी कम स्टार्टअप थे। कृषि और कृषक कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) वित्तीय सहायता प्रदान करके इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है। इसने कृषि स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम भी बनाया है।

इनोवेशन और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत डीए एंड एफडब्ल्यू ने 'नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास' कार्यक्रम लागू किया है।

एक दशक लंबे प्रयासों की सराहना

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान देशभर में स्टार्टअप के इनक्यूबेशन और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभाग की ओर से पांच नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और 24 आरकेवीवाई- एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (आर-एबीआई) नियुक्त किए गए हैं। ये वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। रिपोर्ट में सरकार के एक दशक लंबे प्रयासों की सराहना की गई है। इसमें व्यापक दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया है। इसका फल भी मिला है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों की आय, कृषि बीमा योजनाओं और विस्तारित सिंचाई कवरेज का समर्थन करने वाली पहल से लेकर जैविक खेती को बढ़ावा देने, महिला किसानों को सशक्त बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सेवाओं को डिजिटल बनाने तक सरकार ने किसानों के हित में एक समग्र रणनीति अपनाई है।

कृषि के लिए बजट आवंटन 300% बढ़ा

नौ सालों के दौरान कृषि के लिए बजट आवंटन में 300 फीसदी का उछाल आया है। यह 30,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापक फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण ढाल के रूप में काम करती है, जो अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित होती है। साथ ही वित्तीय बर्बादी को रोका जा सकता है।

बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण भारतीय कृषि वर्तमान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है।

अब दुबई जाना, रहना होगा और आसान

UAE-भारत के बीच जल्द होने जा रहा ये बड़ा समझौता

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

दुबई जाकर वहां नौकरी करने और बसने की चाह रखने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी है। अब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जाना, रहना और व्यापार करना और भी आसान हो जाएगा। इसके लिए भारत और यूएई के बीच लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के तरीकों के अलावा प्रवासन और आवागमन से संबंधित समझौतों को शीघ्र अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई है। नई दिल्ली में मंगलवार को राजनयिक मामलों की संयुक्त समिति (जेसीसीए) की पांचवीं बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने इस बैठक में श्रम, वीजा, प्रवासन, नागरिकता और प्रत्यर्पण सहित अन्य मुद्दों पर समन्वय और सहयोग को मजबूत करने के तंत्र पर व्यापक चर्चा की। मंत्रालय ने कहा, ''दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें लोगों के बीच बेहतर संपर्क को बढ़ावा देने के लिए वीजा सुविधा और प्रवासन तथा आवागमन से संबंधित समझौतों को जल्द पूरा करना शामिल है।'' मंत्रालय ने कहा कि यूएई ने भारतीय प्रवासी श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

आर्थिक, व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी में बढ़ेगा सहयोग

भारत और यूएई अब मिलकर कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, ''दोनों देशों के बीच संबंधों में राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, वाणिज्य, रक्षा, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा, लोगों के आपसी संपर्क समेत आपसी सहयोग के सभी क्षेत्र शामिल हैं।'' पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। यूएई में वर्तमान में 35 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। यह समझौता होने के बाद इस संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है।

भारत और मालदीव के बीच तनातनी से खुश हुआ श्रीलंका

कोलंबो। एजेंसी

श्रीलंका के पर्यटन मंत्री का मानना है कि भारत और मालदीव के रिश्तों में जो तनाव आया है, उसका फायदा उनके देश को मिला है। मंत्री हरिन फर्नांडो ने गुरुवार को कहा कि भारतीयों की ओर से मालदीव यात्रा के बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है, इसका फायदा निश्चित ही श्रीलंका के पर्यटन उद्योग को हो रहा है। फर्नांडो ने इस साल की शुरुआत में भारत और मालदीव के लोगों के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग का हवाला देते हुए सीएनबीसी से कहा कि मालदीव मुद्दा भी हमारी मदद कर रहा है। फर्नांडो ने कहा कि नई दिल्ली और माले के बीच जो हुआ, उसके नतीजे में इस साल मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है।

मालदीव के पर्यटन उद्योग के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार रहा है। 2023 में भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। श्रीलंका के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, अब मालदीव पहुंचने वाले भारतीय घटे हैं और उनका नंबर चीन, रूस, यूके, इटली और जर्मनी के बाद छठे पायदान पर है। दूसरी ओर श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण के आंकड़े कहते हैं कि इस साल जनवरी में 34,400 भारतीय घूमने के लिए श्रीलंका आए, जो पिछले साल जनवरी में आए भारतीयों 13,759 से दोगुने से भी अधिक है। 2024 की पहली तिमाही में भी श्रीलंका आने वाले भारतीयों की संख्या 2023 की इसी अवधि से मुकाबले काफी बढ़ी। हालांकि श्रीलंकाई वीजा की कीमत करीब दोगुनी होने से अप्रैल में पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई।

100 छोटे विमानों का ऑर्डर देने की तैयारी में इंडिगो, एयरलाइन के नाम हो जाएगा रेकॉर्ड

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो कम से कम 100 छोटे विमानों का ऑर्डर देने की तैयारी में है। कंपनी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क को बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके लिए उसे छोटे विमान चाहिए। सूत्रों के मुताबिक उसकी एटीआर, एम्ब्रेयर और एयरबस के साथ बातचीत कर रही है। इंडिगो पहले से ही 78 सीटर 45 एटीआर-72 विमानों को ऑपरेट करती है। इस साल कंपनी को पांच और विमान मिलेंगे। एटीआर फ्रांस और इटली की जॉइंट कंपनी है। सूत्रों का कहना है कि इंडिगो के एटीआर के विमान खरीदने की उम्मीद है। इसके साथ ही इंडिगो दुनिया में सबसे ज्यादा एटीआर विमानों को ऑपरेट करने वाली एयरलाइन बन जाएगी। अभी यह रेकॉर्ड इंडोनेशिया की Wings Air के पास है जो 74 एटीआर विमानों को ऑपरेट करती है।

हालांकि एयरबस ए220 और एम्ब्रेयर के ई-175 विमान भी होड़ में हैं। इंडिगो ने पिछले साल एयरबस को 500 विमानों का ऑर्डर दिया था जो एविएशन के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर था।इंडिगो इंटरनेशनल रूट्स के बाद देश में अपने नेटवर्क को मजबूत कर रह रही है। इससे पहले एयरलाइन ने 25 अप्रैल को घोषणा की कि वह 30 एयरबस A350-900 विमानों का ऑर्डर दे रही है, जो वाइड-बॉडी विमानों के लिए उसका पहला ऑर्डर है। एटीआर टर्बोप्रॉप हैं, जबकि अन्य दो जेट हैं। एटीआर के अलावा, इंडिगो के बेड़े में एयरबस ए320 और ए321 शामिल हैं। साथ ही कंपनी के पास अपने कोडशेयर पार्टनर टर्किश एयरलाइंस के दो बोइंग 777 हैं जो शॉर्ट-टर्म लीज पर हैं। इंडिगो की भारत के घरेलू एयर ट्रैफिक में 60% हिस्सेदारी है। कंपनी कम आबादी वाले शहरों में अवसर देख रही है। हवाई अड्डे के बेहतर बुनियादी ढांचे और सरकार की उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना से इन शहरों में एयर ट्रैफिक की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को विकसित करना और उसे प्रोत्साहित करना है।

घर में इन जगहों पर भूलकर भी न रखें दवाइयां, परिवार का पीछा नहीं छोड़ेगी बीमारियां

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में हर वस्तु का एक निश्चित स्थान होता है। सही जगह पर रखी गई वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जबकि गलत जगह रखी गई वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती हैं। दवाएं भी इसका अपवाद नहीं हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, दवाओं को घर में कुछ खास जगहों पर रखना चाहिए, ताकि वे अपना सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से लोग बिना सोचे समझे कहीं भी दवा रख देते हैं, मगर वास्तु के अनुसार देखा जाए तो ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए आइए आज इस लेख में जानते हैं कि वास्तु के अनुसार घर में किन किन जगहों पर दवाएं नहीं रखनी चाहिए साथ ही ये भी जानेंगे कि घर के किस हिस्से में दवा रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

रसोई घर में नहीं रखना चाहिए दवा

वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में दवा नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसका असर घर के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। इसकी वजह से शारीरिक कष्ट के साथ आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है।

स्नानघर में भी नहीं रखना चाहिए दवाइयां

ज्योतिष के अनुसार स्नानघर यानी बाथरूम घर की वो जगह है जहां दवाइयां तो गलती से भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से दवाओं का सेहत पर उल्टा असर पड़ सकता है। इसलिए स्नानघर में दवाइयां रखने से बचना चाहिए।

सिरहाने नहीं रखना चाहिए

अक्सर लोग दवाओं को अपने बिस्तर पर सिरहाने रख लेते हैं। पर वास्तु के अनुसार ऐसा करने से राहु-केतु का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए ऐसा करने से सभी लोगों को बचना चाहिए।

कहां रखना चाहिए दवाइयां

शीघ्र लाभ लेने के लिए दवाओं को अलमारी या दराज में रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इन सब के अलावा अलमारी में दवाइयां रखने का सबसे अच्छी बात ये है कि वहां वो सुरक्षित रहते हैं और बच्चों की पहुंच से भी दूर रहते हैं।

सोच-समझकर ही धारण करें राशि रत्न

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

राशि रत्न जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को सूट करे, कभी-कभी राशि रत्न भी व्यक्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। अकारक ग्रहों का रत्न पहनना सर्वदा हानिकारक माना जाता है। ज्योतिषी यदि वैद्य है तो रत्न उसकी औषधि। रत्नों को धारण कर भाग्य परिवर्तन किया जा सकता है बशर्ते सही रत्नों का चयन किया जाए। सही एवं अनुकूल रत्न धारण करना अमृत के समान फलदायी है और गलत रत्न धारण करना जहर के समान होता है। राशि रत्न जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को सूट करे, कभी-कभी राशि रत्न भी व्यक्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। जन्मकुण्डली में जिस ग्रह का सम्बंध व्यक्ति के रोग, हानि, व्यय, मृत्यु, पतन आदि से हो, उसे ज्योतिषीय भाषा में अकारक कहा जाता है। अकारक ग्रहों का रत्न पहनना सर्वदा हानिकारक होता है, राशि रत्न धारण करने से पहले उस रत्न के स्वामी की स्थिति का अवलोकन करना चाहिए। अगर उस ग्रह का संबंध मृत्यु भाव से, रोग स्थान आदि अनिष्ट स्थानों से हो, तो राशि रत्न भी नहीं सूट करेगा। जैसे बिना कुंडली के ज्ञान के सिंह राशि वाले सौ लोगों को उनका राशि रत्न माणिक्य पहनाया जाए तो जिनका सूर्य कुंडली में शुभ स्थानों पर बैठा है (या ज्योतिषीय भाषा में जिनका सूर्य कारक है) उनको तो राशि रत्न सूट करेगा। लेकिन यदि सूर्य अनिष्ट स्थान पर बैठा है या जिनका सूर्य अकारक अथवा मारक है, उन्हें राशि रत्न माणिक्य सूट नहीं करेगा, बल्कि मारक और नुकसानदायक सिद्ध होगा, अतः सोच-समझ कर ही रत्न धारण करें।

राशि रत्न का सही चयन देता है चमत्कारिक लाभ

सही समय और सही नक्षत्र के अनुसार सही रत्न धारण करने से जीवन में चमत्कारी लाभ का सृजन होता है और व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बहार आने लगती है, जीवन आराम से व्यतीत होता है। शुभ एवं अनुकूल रत्न धारण करने से व्यक्ति का भाग्य तो प्रबल होता ही है साथ ही साथ कई बीमारियों से लड़ने की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। राशियों के अनुसार राशि रत्न धारण करते समय राशि के स्वामी की स्थिति का अवलोकन अवश्य करना चाहिए।

1. अगर आपकी राशि मेष है और आप राज्य कृपा और बुद्धि बल, संतान सुख, प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मंगल की शुभ स्थिति को देखकर ही मूंगा धारण करें।

2. आप वृष राशि वाले जातक हैं और आपको मानसिक शांति, सुख, गृह भूमि लाभ, माता का सुख तथा वाहन सुख की अभिलाषा है तो आप शुक्र की शुभ स्थिति देखकर हीरा या जरकन धारण करें तो आपको निश्चित लाभ होगा।

3. जिनकी कुंडली में बुध कारक हो उन मिथुन राशि वालों को पन्ना रक्षा कवच के रूप में काम करता है। मिथुन राशि वाले पन्ना धारण करने से धन, शिक्षा, यश, मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं।

4. कर्क अगर आपकी राशि है और चन्द्रमा शुभ भूमिका में है, तो आप निश्चित ही मोती धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने से मानसिक शांति, उलझनों से छुटकारा होने लगता है।

5. जिनकी कुण्डली में सूर्य कारक हो उन सिंह राशि वालों के लिए माणिक्य रामबाण का काम करता है, इसे धारण करने से कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, माणिक्य विजय श्री दिलाता है।

6. जिनकी कुंडली में बुध कारक हो उन कन्या राशि वालों को पन्ना धन, दौलत, नौकरी और मान-सम्मान दिलाता है, साथ ही साथ मन की शांति भी प्रदान करता है और पन्ना चर्म रोग से निजात भी दिलाता है।

7. तुला राशि वालों को शुक्र की शुभ स्थिति देखकर हीरा धारण करना चाहिए ताकि ऐसे लोग भाग्य में लिखे जीवन के हर सुख-वैभव को प्राप्त कर सकें।

8. वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में यदि मंगल शुभ स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्ति यदि मूंगा धारण करते हैं तो उन लोगों को अपार सफलता मिलती है, जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है।

9. धनु राशि वाले जातकों को बृहस्पति शुभ एवं कारक होने पर पीला पुखराज धारण करना चाहिए ताकि जीवन की हर समस्याओं का समाधान देवगुरू बृहस्पति की कृपा से हो सके।

10. मकर राशि वालों को कुण्डली में शनि की शुभ स्थिति देखकर ही नीलम धारण करना चाहिए ताकि जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से निजात मिल सके।

11. शनि अगर कुंभ राशि वालों की कुंडली में कारक अवस्था में हो और कुंभ राशि वाले नीलम धारण करें तो उनके रुके हुए सभी कार्य शीघ्र ही बनने लगते हैं।

12. अगर आप मीन राशि के हैं और जन्मकुण्डली की गणना के अनुसार बृहस्पति अकारक नहीं है तो इसके लिए आप पुखराज अथवा उसका उपरत्न सुनहला धारण करें, इसे धारण करने से आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।

इस दिन मनाई जाएगी शनि जयंती जानें कैसे मिलेगा शनि देव का आशीर्वाद

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए ज्येष्ठ अमावस्या का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है. शनि देव सेवा और कर्म का कारक माना जाता है. इस दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. शनि देव लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. इसलिए, शनि जयंती पर लोग शनि देव से अच्छे कर्म करने और जीवन में सफलता पाने की प्रार्थना करते हैं. इस बार शनि जयंती 6 जून 2024, गुरुवार के दिन मनाई जाएगी. आइए जानते हैं कि शनि जयंती के दिन कौन से काम करके आप शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं.

शनि जयंती के दिन करें ये काम

इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद शनि देव की विधिपूर्वक पूजा करें. इस दिन शनि देव का सरसों के तेल और काले तिल से अभिषेक करें. शनि मंदिर जाएं और उनके दर्शन करें.

अगर आपकी कुंडली में शनि दोष से है तो इससे मुक्ति के लिए शनि जयंती के दिन शनि मंदिर में जाकर पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें. शनि चालीसा का पाठ करें या शनि देव के मंत्रों का जाप करें.

इस दिन काले कुत्ते को सरसों

के तेल से बनी रोटी खिलाएं. इस दिन कौवों को खाना खिलाना भी शुभ माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं.

मान्यता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनि देव कभी परेशान नहीं करते. ऐसे में शनि जयंती के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक दान करना चाहिए और सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए.

शनि दोष से मुक्ति के लिए शनि जयंती के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए. इससे शनि देव जल्द प्रसन्न होकर भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं.

गरीबों की सेवा करने से भी शनि देव की कृपा प्राप्त होती है. शनि जयंती के दिन गरीबों को काला तिल, वस्त्र, उड़द की दाल, जूते-चप्पल और कंबल का दान करना चाहिए.

शनि जयंती के दिन उपवास रखना चाहिए. अगर संभव न हो तो पूरे दिन में केवल एक बार भोजन करें. काले कपड़ पहनकर और शनि देव की पूजा करने से लाभ होता है.

वेसी योग क्या है, कुंडली में ये कैसे बनता है, किन ग्रहों का पड़ता है प्रभाव?

वेशी योग सूर्य से बनने वाला राजयोग हैं. ज्योतिष शास्त्र में वेशी योग एक बहुत ही दुर्लभ और अत्यधिक प्रभावी ग्रह संयोजन माना जाता है.

पंडित कपिल पाराशर
बनारस वाले ज्योतिष आचार्य वास्तु विशेषज्ञ

कुंडली में सूर्य के अगले घर में किसी ग्रह के स्थित होने पर वेशी योग बनता है.

जिन जातकों की कुंडली में सूर्य के पिछले घर में किसी ग्रह के होने पर वसी योग बनता है, लेकिन यह ग्रह चंद्रमा, राहु और केतु नहीं होने चाहिए, तब जाकर इस योग से शुभ फल की प्राप्ति होती है.

इस योग के होने पर व्यक्ति अच्छा वक्ता और धनवान होता है. वेशी योग वाले व्यक्ति आशावादी, समृद्धशाली, उदार होते हैं. वेशी राजयोग वाले जातकों को जीवन की शुरुआत में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

जिन लोगों की कुंडली में यह राज योग होता है, वे स्वयं में ही ज्ञान का भंडार होते हैं.

ग्रोथ और डिविडेंट पेआउट स्ट्रेटजी के साथ

बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड का एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च

मुम्बई/पुणे। आईपीटी नेटवर्क

बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (बजाज फिनसर्व एएमसी) ने बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के लॉन्च की घोषणा की। यह एक ओपन-एंडेड स्कीम है जो निवेशकों को विविध निवेश अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह फंड उच्च लाभांश उपजदेने वाली स्ट्रेटजी के साथ इक्विटी, गतिशील अवधि प्रबंधन के साथ ऋण, कमोडिटी और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) सहित विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में एक्सपोजर प्रदान करता है।

बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में अलग-अलग आवंटन के साथ निवेश करता है। यह 35% से 80% तक इक्विटी आवंटन के साथ एक विविध पोर्टफोलियो बनाए रखता है और इसके साथ ही, यह लाभांश उपज रणनीति, मल्टी-थीम और मल्टी-सेक्टर दृष्टिकोण और मल्टी-कैप ओरिएंटेशन को नियोजित करता है। गुणवत्ता पोर्टफोलियो और सुरक्षा-प्रथम दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, मैक्रो और मात्रात्मक इनपुट के साथ गतिशील अवधि प्रबंधन को नियोजित करते हुए, यह फंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 10% से 55% आवंटित करता है। इसके अलावा, यह वस्तुओं के लिए 10% से 55% आवंटित करता है, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और एक्सचेंज-ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए एक्सपोजर प्रदान करता है, जिससे अपसाइड पोटेंशियल ऑफर करता है और इक्विटी संबंधी अस्थिरता के मामलों में बचाव करता है। इसके अलावा, फिक्स्ड इन्कम, डायवर्सिफिकेशन और अवसरवादी दृष्टिकोण के लिए निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह फंड आरईआईटी या इनविट को 0% से 10% आवंटित कर सकता है। प्रोडक्ट लॉन्च के मौके पर, बजाज फिनसर्व एएमसी के सीईओ, श्री गणेश मोहन ने कहा, 'बजाज फिनसर्व मल्टी एसेट एलोकेशन फंड निवेशकों को एक ही निवेश के ज़रिये कई परिसंपत्ति वर्गों तक पहुंचने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह भारत का पहला मल्टी एसेट फंड है जो लाभांश देने वाली रणनीति (dividend yield strategy) प्रदान करता है।

जीई एयरोस्पेस ने जीई एयरोस्पेस फाउंडेशन को लॉन्च किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

जीई एयरोस्पेस ने हाल ही में जीई एयरोस्पेस फाउंडेशन के लॉन्च की घोषणा की है। ये कंपनी के इतिहास में एक नया अध्याय है जो पिछले जीई फाउंडेशन के 100 से ज्यादा सालों की विरासत पर आधारित है। जीई एयरोस्पेस फाउंडेशन की परोपकारी नीतियां और कार्यक्रम कंपनी के कार्यबल के विकास, आपदा राहत और जीई एयरोस्पेस के कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने में योगदान करेंगी। इससे जीई एयरोस्पेस से जुड़े 'लोगों का उत्थान करने' (लिफ्ट पीपल अप) के कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

दक्षिण एशिया में, जीई एयरोस्पेस फाउंडेशन समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए आपदा राहत, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को सपोर्ट करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ काम करना जारी रखेगा। पिछले 10 सालों में दक्षिण एशिया को फाउंडेशन से संबंधित कुल अनुदान में 12 लाख अमेरिकी डॉलर मिले हैं। इसमें अनुदान और संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं। इन प्रयासों से बेंगलुरु, पुणे और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों के लोगों को फायदा हुआ है।

जीई एयरोस्पेस के चेयरमैन और सीईओ एच. लॉरेंस कल्प, जूनियर ने कहा, 'हम जहां रहते हैं और काम करते हैं उसके आसपास रहने वाले लोगों को सपोर्ट करने और उनको मजबूत बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। फाउंडेशन के कार्यक्रम तीन मुख्य क्षेत्रों पर फोकस करेंगे। फाउंडेशन 2030 तक अपने नए कार्यक्रमों पर 2.2 करोड़ डॉलर से ज्यादा खर्च करेगा। यह फाउंडेशन मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत और अलग-अलग तरह के काम करने वाले वर्कफोर्स तैयार करने और दुनिया भर में अपना सकारात्मक असर दिखाने वाले और कर्मचारियों के बीच सहभागिता को बढ़ाने वाले मानवीय और सामुदायिक कार्यक्रमों में निवेश करने जैसे काम करेगा। इस मौके पर जीई एयरोस्पेस फाउंडेशन के चेयरमैन मेघन थुरलो ने कहा, 'हमें भविष्य के लिए मजबूत वर्कफोर्स, आपदा राहत और कर्मचारी अनुदान को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ परोपकारी कामों के इस अगले अध्याय की देखरेख करने पर बेहद गर्व है।

पॉलीकैब का एक्सपर्ट्स ऐप के साथ इलेक्ट्रीशियन को इंस्टेंट रिवार्ड और इंस्टेंट रिडेम्पशन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत की सबसे बड़ी वायर और केबल निर्माता और सबसे तेजी से बढ़ती एफएमईजी कंपनियों में से एक पॉलीकैब ने नए 'पॉलीकैब एक्सपर्ट्स' को लॉन्च करने की घोषणा की है। अपनी तरह का यह पहला प्लेटफॉर्म दरअसल देश के इलेक्ट्रीशियन कम्युनिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि उन्हें भी डिजिटल परिवर्तन की लहर में शामिल होने का एक और अवसर मिल सके। पॉलीकैब एक्सपर्ट्स का उद्देश्य पूरे भारत में इलेक्ट्रीशियन समुदाय को सशक्त बनाना और उनके जरिये ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। यह ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो अपने ग्राहकों को लाभ और पुरस्कारों का एक व्यापक सूट प्रदान करके उनके लिए पॉइंट अर्जित करने और रिडेम्पशन दोनों सुविधाएं प्रदान करता है। पॉलीकैब एक्सपर्ट प्रोग्राम के पास 1.5 लाख इलेक्ट्रीशियन और लगभग 1 लाख रिटेलर के साथ एक मौजूदा ऐप है जिन्हें नए ऐप में माइग्रेट किया जाएगा।

पॉलीकैब एक्सपर्ट्स ऐप एक इनोवेटिव रिवार्ड सिस्टम पेश करता है जो इलेक्ट्रीशियन और रिटेलर को पॉलीकैब उत्पादों पर मुद्रित लॉयल्टी कोड को स्कैन करके आसानी से पॉइंट अर्जित करने की सुविधा देता है। इन संचित अंकों को तुरंत उनके बैंक खातों में भुनाया जा सकता है, इस तरह उन्हें पॉलीकैब के प्रति उनकी वफ़ादारी के लिए एक ठोस और तत्काल प्रोत्साहन मिलता है।

नए पॉलीकैब एक्सपर्ट्स प्लेटफ़ॉर्म के हिस्से के रूप में नामांकित इलेक्ट्रीशियन तीन-स्तरीय लॉयल्टी प्रोग्राम के माध्यम से विशेष लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक स्तर पर विशेष लाभ अनलॉक होते हैं जो इलेक्ट्रीशियन समुदाय के कारोबार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे-जैसे वे स्तरों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रीशियन अपने और अपने जीवनसाथी के लिए चिकित्सा बीमा, अपने बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के अवसर और अपने पेशेवर प्रदर्शन और अतिरिक्त अंकों को बढ़ाने के लिए वेलकम रिवार्ड्स सहित विशेष लाभ हासिल कर सकते हैं।

यूवा मास्टर स्ट्रोकः पूरे भारत में रचनात्मकता और प्रतिभा का जश्न

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

हाउस ऑफ नवनीत एजुकेशन से यूवा स्टेशनरी (युवा स्टेशनरी), पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में आयोजित 'यूवा मास्टर स्ट्रोक' प्रतियोगिता के सफल समापन की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रही है। युवा मास्टर स्ट्रोक एक विशेष मंच है,जो छात्रों को ड्राइंग के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को उजागर करने का अधिकार देता है। दो दशकों की विरासत के साथ, यह वर्ष इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की 20वीं वर्षगांठ था। 2023 संस्करण में 22 राज्यों के कुल 5251 स्कूलों ने उत्साह पूर्वक प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें लगभग 13.6 लाख छात्रों ने अपनी कलात्मक प्रकृति और कल्पना का प्रदर्शन किया ।प्रतिभागियों को तीन आयु समूहों में वर्गीकृत किया गया था, प्रत्येक को उनके चित्र के लिए विशिष्ट विषय सौंपे गए थे। यूवा के मुख्य रणनीति अधिकारी अभिजीत सान्याल ने कहा, 'हम भारत में इतने सारे राज्यों में छात्रों की रचनात्मकता और प्रतिभा का जश्न मनाते हुए यूवा मास्टर स्ट्रोक के एक और सफल संस्करण को देखकर खुश हैं।यह प्रतियोगिता न केवल युवा कलाकारों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करती है,बल्कि कलात्मक अभिव्यक्ति और सराहना की संस्कृति को भी बढ़ावा देती है।मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूं।' यूवा का मानना है कि ड्राइंग, अभिव्यक्ति की एक सार्वभौमिक भाषा होने के नाते, छात्रों को अपने विचारों और भावनाओं को चुपचाप संवाद करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, उनकी सहज कलात्मक प्रतिभाओं का पोषण करता है।यूवा मास्टर स्ट्रोक उसी का एक प्रमाण है।

टाटा मोटर्स ने ऑल-न्यू टाटा ऐस ईवी 1000 को लॉन्च किया

इलेक्ट्रिक उत्पादों की श्रृंखला को बेहतर बनाया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

टाटा मोटर्स, भारत में कमर्शियल वाहनों के सबसे बड़े निर्माता, ने आज ऑल-न्यू ऐस ईवी 1000 को लॉन्च कर अपने ई-कार्गो मोबिलिटी सोल्यूशंस को मजबूत किया है। उपभोक्ताओं को उनके घर या ऑफिस तक डिलीवरी देने में क्रांति लाने के मकसद से विकसित, इस शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाले मिनी ट्रक में एक टन तक सामान को लोड करने की क्षमता दी गई है। एक बार चार्ज करने पर यह मिनी ट्रक 161 किमी की रेंज प्रदान करता है, जिसे प्रमाणित किया जा चुका है। ऐस ईवी को उपभोक्ताओं के फीडबैक और जरूरतों को देखते हुए विकसित किया गया है। यह नया वैरिएंट एफएमसीजी, बेवरेजेस, पेंट एंड लुब्रिकेंट्स,एलपीजी और डेयरी जैसे कई क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करता है। देश भर में टाटा ईवी के 150 से ज्यादा व्हीकल सपोर्ट सेंटर हैं। ऐस ईवी एडवांस बैटरी, फ्लीट ऐज टेलीमेटिक्स सिस्टम और बेहतरीन संचालन समय के लिए मजबूती से ट्रक की पूरी यूनिट और पार्टर्स को एकत्र करता है। ऐस ईवी टाटा यूनिवर्स की असीम क्षमताओं का लाभ उठाता है। टाटा ग्रुप की प्रासंगिक कंपनियों से साझेदारी करता है। उपभोक्ताओं को संपूर्ण मोबिलिटी सोल्यूशन प्रदान करने के लिए कंपनी की देश के प्रमुख फाइनेंसरों से भी साझेदारी है। यह सामान रखने के लिए अलग-अलग डेक के साथ उपलब्ध होगा। यह देश भर में टाटा मोटर्स के कमर्शियल वाहन के सभी डीलरों के पास उपलब्ध होगा। टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स में एससीवी और पीयू डिविजन के वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड श्री विनय पाठक ने बताया, 'पिछले दो सालों से हमारे ऐस ईवी के उपभोक्ता बेमिसाल अनुभव का लाभ ले रहे हैं, जो एक ही समय में उन्हें मुनाफे के साथ उनके बिजनेस में स्थिरता प्रदान करता हैं। शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाले यह व्यावसायिक वाहन लोगों के ऑर्डर की डिलिवरी उनके घर पहुंचाने के क्षेत्र में राजदूत बन गए हैं।

बिरला ओपस के साथ पेंट्स के नए युग में प्रवेश करें!

इंदौर/मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

आदित्य बिरला ग्रुप ने फरवरी 2024 में 'बिरला ओपस' के लॉन्च के साथ पेंट उद्योग में प्रवेश किया था। बिरला ओपस की शुरुआत के साथ आदित्य बिरला ग्रुप तेजी से बढ़ते हुए 80,000 करोड़ रुपये के भारतीय डेकोरेटिव पेंट उद्योग में प्रवेश कर गया, जिसके लिए कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपये का बड़ा अग्रिम निवेश किया। 15 मई, 2024 से कंपनी के मजबूत डीलर नेटवर्क द्वारा 'बिरला ओपस' के सभी उत्पाद पूरे देश में उपलब्ध होंगे। विभिन्न स्थानों पर आयोजित अपनी पिछली एक्स्पो और डीलर मीट्स को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद बिरला ओपस अब बाजार में उतरने के लिए उत्साहित है और हम विभिन्न स्थानों पर तेजी से अपना विस्तार कर रहे हैं। बिरला ओपस सभी सेगमेंट्स में विस्तृत पोर्टफोलियो प्रदान करता है, जिसमें इंटीरियर, एक्सटीरियर, वाटरप्रूफिंग, इनैमल पेंट्स, वूड फिनिश, और वॉलपेपर सहित सभी श्रेणियों में बेहतर उत्पाद शामिल हैं। बिरला की विरासत और ओपस की क्रिएटिविटी के साथ बिरला ओपस का उद्देश्य पेंट उद्योग में इनोवेशन लाना है। बिरला ओपस के सीईओ, रक्षित हर्वे ने कहा, ''बिरला ओपस आदित्य बिरला ग्रुप के लिए एक रणनीतिक पहल है। इसका उद्देश्य पेंट्स उद्योग में एक नया युग शुरू करना है। हम विभिन्न शहरों में वितरण और अपने नेटवर्क को मजबूत बनाकर इसकी उपलब्धता बढ़ाना चाहते हैं। एक्स्पो में हमें अपनी डीलर मीट्स, पेंटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, और इंटीरियर डिज़ाईनर्स से बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। हमने विशाल स्तर पर कॉन्ट्रैक्टर्स को सैंपल प्रदान किए, और वो सभी बिरला ओपस पेंट्स का उपयोग कर अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए उत्साहित हैं।'' बिरला ओपस अपनी टेक्नोलॉजिकल विशेषज्ञता के साथ पेंट उद्योग में एक इनोवेटर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाते हुए ग्राहकों के बीच निष्ठा और विश्वास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

आईआईएमए वेंचर्स का इंदौर स्मार्ट सिटी एक्सेलरेटर स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

आईआईएमए वेंचर्स (पूर्व में आईआईएमए-सीआईआईई) ने इंदौर स्मार्ट सिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के अपने पहले समूह में इंदौर से 14 स्टार्टअप्स को अपने सहयोग की घोषणा की है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों और स्मार्ट सिटी इंदौर के सहयोग से इस प्रोग्राम का उद्देश्य स्टार्टअप्स को बिज़नेस मॉडल्स एवं सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहकों की सहभागिता के लिए जरूरी प्रस्ताव बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है।

इस प्रोजेक्ट के लिए भारत में रजिस्टर्ड और स्थित 100 स्टार्टअप्स से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका उद्देश्य इंदौर स्मार्ट सिटी के लिए शहरी मोबिलिटी, स्वच्छता, नागरिक सुरक्षा व बचाव, और एयर क्वालिटी से संबंधित क्षेत्रों में इनोवेटिव समाधान तलाशना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य अरली-स्टेज स्टार्टअप्स को शहरी लोकल बॉडीज़ (यूएलबी) के लिए अपने पायलट चलाने में मदद करना है ताकि उनके समाधानों की पुष्टि हो सके। इंदौर स्मार्ट सिटी एक्सेलरेटर ने इंदौर स्मार्ट सिटी के साथ गठबंधन में इंदौर में एक तीन दिवसीय गहन बूट कैंप चलाया।

इन स्टार्टअप्स को बिज़नेस मॉडलिंग, यूनिट इकॉनॉमिक्स, बी2जी सेल्स, सरकारी टेंडर्स का आवेदन करने और एंजेल निवेशकों के निवेश के लिए तैयार होने जैसे विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षित किया गया, और उन्हें विषय के विशेषज्ञों के साथ वन-टू-वन मेंटरिंग सत्र और ऑफिस में काम करने के अवसर प्रदान किए गए। इसके बाद वर्चुअल डायग्नोस्टिक पैनल्स और मेंटरिंग सत्रों का आयोजन हुआ।

इंदौर स्मार्ट सिटी द्वारा इस समूह से 3 स्टार्टअप्स को पायलट के लिए चुना गया: ऑमसैट टेक्नोलॉजीज़ (https://www.aumsat.com/): श्री रिद्धीश सोनी, एक्स-इसरो द्वारा गठित टीम ने पानी की पाईपलाईंस में लीकेज का पता लगाने के लिए समाधान विकसित किया, जो आईओटी-आधारित समाधानों और सैटेलाईट इमेज का उपयोग कर जमीन के 10 फीट अंदर तक लीकेज की जगह का पता लगा लेता है। इस इनोवेशन का उद्देश्य पानी के अनुमानित 40 प्रतिशत नुकसान को कम करके 15 प्रतिशत पर लाना है।

आर्क रोबोटिक्स (https://arcrobotics.in/): डायनामिक इंजीनियर्स की एक युवा टीम ने छः डिग्री की स्वतंत्रता के साथ वाहन पर लगने वाले रोबोट का विकास किया है, जो सीवेज पाईपलाईंस का पता लगाकर उन्हें साफ कर सकता है। इससे भारत में सीवेज की सफाई में मानव हस्तक्षेप की जरूरत खत्म हो जाएगी।

पोड पिटारा (https://podpitara.com/about): टीम ने शहर की सार्वजनिक बसों में आईओटी-इनेबल्ड रेडियो स्थापित करने के लिए इंदौर प्रशासन के साथ गठबंधन किया है। यह इंदौर के नागरिकों के बीच जागरुकता बढ़ाने और शहर से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान करने के लिए प्रयोग के तौर पर यूएलबी की मदद करेगा।

इसके अलावा एक अन्य स्टार्टअप इलेक्टिका में भी आईआईएमए वेंचर्स ने अपने एक रीज़नल ईकोसिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से निवेश किया है। इलेक्टिका ने एक ऑटोमेटेड बैटरी स्वैपिंग सॉल्यूशन का विकास किया है, जिसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में बैटरी-स्वैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। इसके अलावा, समूह के 2 स्टार्टअप्स पर 5 लाख रुपये तक की ग्रांट के लिए विचार किया जाएगा।

अप्रैल 2024 के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि

निरंतर ऑर्डर बुकिंग वृद्धि की कुंजी बनी - फियो

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

फियो के अध्यक्ष श्री अश्विनी कुमार ने अप्रैल, 2024 के माल निर्यात आंकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नए वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत सकारात्मक नोट पर 34.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ हुई और अप्रैल 2023 के 34.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी यह अच्छा संकेत है। यह न केवल लचीले निर्यात क्षेत्र के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, बल्कि प्रयासों और कड़ी मेहनत को भी दर्शाता है। श्री कुमार ने कहा कि लाल सागर संकट और इजरायल-हमास संघर्ष सहित विभिन्न प्रमुख भू-राजनीतिक तनावों के साथ चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध ने भी भारतीय निर्यातकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य को बहुत कठिन बना दिया है। हमें उम्मीद है कि यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, पश्चिम एशिया और अमेरिका में मांग में सुधार के साथ निर्यात में बेहतर वृद्धि के आंकड़े दिखने लगेंगे, जिससे ऑर्डर बुकिंग में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और यह चमड़ा और चमड़ा उत्पाद, जूते और परिधान सहित निर्यात के श्रम-प्रधान क्षेत्र में सुधार के संकेत के रूप में आया है। नए ऑर्डरों से भी कुछ सकारात्मक शुरुआत की उम्मीद है, फियो अध्यक्ष श्री कुमार ने दोहराया कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध देश के निर्यात क्षेत्र के लिए एक अवसर के रूप में आ सकता है।

फियो प्रमुख ने कहा कि जिन प्रमुख क्षेत्रों ने अप्रैल 2024 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाई है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, पेट्रोलियम उत्पाद, प्लास्टिक और लिनोलियम, सूती धागा/फैब्स/मेड-अप, हथकरघा उत्पाद आदि, मसाले, अनाज की तैयारी और विविध प्रसंस्कृत वस्तुएं, चाय, कॉफी, तंबाकू, कालीन और हस्तशिल्प (हस्तनिर्मित कालीन को छोड़कर) शामिल हैं। माह के दौरान (वस्तुओं और सेवाओं) का कुल निर्यात बढ़कर 64.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो अप्रैल 2023 में 60.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जबकि कुल आयात अप्रैल 2023 में 63.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में बढ़कर 71.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे व्यापार घाटा बढ़ अप्रैल 2023 के 2.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 6.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। श्री कुमार ने यह भी कहा कि यद्यपि मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों, सोना, दालों और वनस्पति तेल के कारण आयात में वृद्धि हुई है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों और सोने के आयात में वृद्धि से कुछ समय के अंतराल के बाद पेट्रोलियम उत्पादों और रत्न और आभूषणों के निर्यात में वृद्धि होगी।

फियो अध्यक्ष श्री अश्विनी कुमार ने दोहराया कि ब्याज सहायता समर्थन और ब्याज समकारी योजना को जारी रखने के साथ तरलता के मोर्चे पर कदम उठाना समय की मांग है। इसके अलावा, समुद्री बीमा की उपलब्धता और माल ढुलाई शुल्क में तर्कसंगत वृद्धि सुनिश्चित करके मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिति, लाल सागर संकट की चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा आसान और कम लागत वाले ऋण, विपणन सहायता और ब्रिटेन, पेरू और ओमान के साथ कुछ प्रमुख एफटीए के शीघ्र समापन की भी आवश्यकता है।

धानुका ने खरपतवारनाशक 'पर्ज' मध्य प्रदेश में लांच किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

अग्रणी कृषि रसायन कंपनी, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने जापान की निसान केमिकल कॉर्पोरेशन के साथ रणनीतिक सहयोग में,मध्य प्रदेश राज्य के साथ-साथ विश्व स्तर पर एक उच्च-तकनीक खरपतवारनाशक 'पर्ज' का अनावरण किया। पर्ज संकरी और चौड़ी दोनों तरह की पत्तियों को नियंत्रित करने में काफीप्रभावी है, और यह फसल पैदावार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभासकता है, जिससे मध्य प्रदेश के किसान लाभान्वित होंगे।

कंपनी ने राज्य में कीटनाशक 'लानेवो' और बायो-फर्टिलाइजर 'माईकोरसुपर' को भी लांच किया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के कृषि क्षेत्र ने पिछले दशक में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्ष 2013-14 से लेकर 2023-24 के दौरान मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र ने इन दस वर्षों के राष्ट्रीय औसत 3.9 प्रतिशत के मुकाबले 6.1 की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है।

परेशान करने वाले कई तरह के खरपतवार को नियंत्रित करने मेंखरपतवारनाशक पर्ज किसानों की मदद करता है। यह नया प्रोडक्टडिजिटेरिया सेंगुइनालिस, इचिनोक्लोआ क्रूसगैली, गूज घास (एलुसीनइंडिका) और मकरा घास (डैक्टाइलेक्टेनियम एजिपटियम) जैसे संकरीपत्तियों के खरपतवार (एनएलडब्ल्यू) और हरित मंजरी (अकलिफाईडिका), टांडला (डिगेरा अर्वेन्सिस), पुनर्नवा (बोएरहविया डिफ्यूसा) औरगाजर घास (पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस) जैसे चौड़ी पत्तियों के खरपतवार(बीएलडब्ल्यू) दोनों को प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रण में रखता है। पर्ज, लानेवो और माईकोर सुपर ने धानुका की प्रोडक्ट पेशकश, खासकरइसके कीटनाशक पोर्टफोलियो को काफी मजबूत दी है।

पर्ज के लांच के अवसर पर उपस्थित धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के वाइस-चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एम के धानुका ने नवाचार के प्रति कंपनी की अनवरत प्रतिबद्धता और गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्टों पर कंपनी का खास ध्यान को रेखांकित किया। 'पर्ज का लांच किसानों को बेहतर फसल पैदावार देने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट लांच करने की हमारी प्रतिबद्धता की दिशा में लिया गया एक और कदम है। देश का अग्रणी कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते मध्य प्रदेश हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण राज्य है,' उन्होंने कहा। धानुका ने 'लानेवो' को भी लांच किया, जो अनोखे तरीके से कार्य करते हुए चूसने और चबाने वाले कीटों के विरुद्ध अधिक फसल सुरक्षा के लिए एक साथ दो लाभ प्रदान करता है। इसे प्रतिरोधक क्षमता विकास को न्यूनतम करने और स्वस्थ फसल एवं अधिक पैदावार देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।

चीन, पाकिस्तान पर नजर.. भारत बनाने जा रहा है तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर

नई दिल्ली। एजेंसी

हाल ही में चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान टेस्ट के लिए समुद्र में उतारा। इसी बीच भारत में भी तीसरे विमानवाहक युद्धपोत की डिमांड तेजी से उठने लगी। अब इस मुद्दे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शुरू कर देगा। हम केवल उसी पर नहीं रुकेंगे। इसके बाद हम पांच, छह और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। एक इंग्लिश न्यूजपेपर को दिए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि नौसेना में लंबित प्रस्ताव का वो जिक्र कर रहे। इसमें घ्ए विक्रांत के समान आकार का एक और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्रस्ताव है।

अभी भारत के पास हैं दो एयरक्राफ्ट कैरियर- आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन था और जिसे सितंबर 2022 में कमीशन किया गया था। आईएनएस विक्रांत के अलावा भारत के पास एक और कैरियर है, जिसका नाम आईएनएस विक्रमादित्य है। इसे 2013 में रूस से मंगाया गया था। समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर रखना लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है, इसके जरिए डेक से फाइटर जेट को लॉन्च और रिकवर कर सकते हैं। अब तक, भारत भी तीन विमानवाहक पोत रखने की बात करता रहा है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।